







# संपादकीय खाद्य सामग्री में मिलावट से जूझता समाज..

# रिपोर्टों के पीछे मकासद क्या है

ऐसी रिपोर्टें कई दशक से जारी हो रही हैं। अब यह कहने का आधार है कि इनसे गरीबी की ठोस समझ बनाने में कोई मदद नहीं पली है। इसलिए अब यह सवाल उठाने का वक्त है कि इन रिपोर्टों पीछे मकसद क्या है? बीते हफ्ते के अरंभ में विश्विक गरीबी र में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई। सप्ताहांत में संयुक्त राष्ट्र ने इसी अंबंध में अपनी रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी स्थित ऑक्सफॉर्ड वर्टनी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव पिछले कई वर्षों से रीब लोगों की संख्या के बारे में अपना साझा अनुमान जारी कर रहे हैं। अपनी ताजा रिपोर्ट में उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि हाँ 23 करोड़ 40 लाख लोग चरम गरीबी में जी रहे हैं। विश्व बैंक ने ये संख्या 13 करोड़ 40 लाख बताई थी। ये दोनों आधिकारिक संस्थाएं हैं। इनके अलावा कुछ एनजीओ भी अपना अनुमान जारी करते हैं। उनसे भी अलग संख्या सामने आती है। ऐसी रिपोर्ट कई दशक से जारी हो रही हैं। इसलिए अब यह कहने जा आधार है कि इनसे गरीबी को समझने या उससे लोगों को दृढ़ि दिलाने के बारे में कोई ठोस सोच नहीं बनती है। उलटे भ्रम दा होता है। इसलिए अब यह सवाल उठाने का वक्त है कि इन रिपोर्टों को तैयार करने के पीछे मकसद क्या है? उद्देश्य दुनिया में गरीबी खत्म करना है, तो फिर ये संस्थाएं न्यूनतम और भ्रामक माने क्यों अपनाती हैं? नव-उदारवादी दौर के पहले एक मान्य गॉमूला व्यक्तियों को उपलब्ध कैलोरी होती थी। भारत में गांवों में जन लोगों को रोजाना 2200 और शहरों में 2100 से कम कैलोरी उपलब्ध थी, उन्हें गरीब समझा गया था। अनेक गंभीर वर्षशास्त्रियों दिखाया है कि आज इस कैलोरी उपलब्धता से वचित लोगों की संख्या तब से ज्यादा है। वजह यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी सेवाओं का निजीकरण होने का बोझ लोगों की निजी आमदनी पर पड़ा है। इस कारण उन्हें अपनी जरूरतों में बहुती करनी पड़ी है। इस बात के आधिकारिक ऑक्सफॉर्ड हैं कि हुत से गरीब लोगों ने अपने भोजन में कटौती की है। जबकि रक्षा एवं इलाज जैसी अनिवार्यताओं पर बढ़े खर्च की गणना खर्च मात्रा में करके विश्व बैंक करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से उठा देता है।

आलेख

**कांग्रेस फिर एक बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने को तैयार**

आंनेल चतुर्वेदी

कांग्रेस फिर एक बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने को तैयार होती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार की बजह टटोलने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो तीन सदस्यीय टीम बनाई उसमें शामिल नेता शायद ऐसा ही जबाब अपने नेता को देने की तैयारी में हैं। यह अलग बात है कि इस फैक्ट्री फ़ाइंडिंग कमेटी में हरियाणा के पूर्व सीएम और इस चुनाव का सारा दारोमदार संभालने वाले भूपेन्द्र सिंह हुड़ा शामिल नहीं किए गए हैं पर जिन्हें जिम्मदारी दी गई है उनके नाम उजागर भले नहीं किए गए हैं पर कांग्रेसी सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो दो नेता जाँच के लिए हरियाणा भेजे गए उन्हें ज़मीनी स्तर पर लोगों से इस हार के कारणों को टटोलने के निर्देश दिए गए हैं। पर भला हार की इस निराशा में नेताओं की कितनी हिम्मत रहेगी घर-घर घूम कर हार की बाबत लोगों से पूछने की और सवाल उम्र का भी है सो आराम भी ज़रूरी होगा ही। तभी अगर दिल्ली के कांग्रेसी ही यह कहने लगें कि फैक्ट्री पता करने गए ये दो नेता होटल में ठर मोबाइल या फिर फ़ोन पर लोगों से बात कुछ पूछने के नाम पर यह पूछ रहे हों कि कि क्या हम ईवीएम की बजह से हारे हैं। तो नेता पर शक तो कोई भी कर ही सकता है ना! तब भला फैक्ट्री फ़ाइंडिंग का मतलब भी क्या रह जाता है। अब भला हरियाणा हार का घूँट तो कांग्रेसी पाकर रह जाएंगे पर चिंता तो बाकी उन सूबों की सता रही है जहां हरियाणा हार का असर पड़ता कांग्रेसियों को दिख रहा है। भला होता कि गुटबाज़ी छोड़ कांग्रेसी हरिया जीतते और फिर बाकी सूबों में सीना तान कर चुनाव लड़ रहे होते। हरियाणा में जीत और जम्मू-कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन से भाजपा ही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्साहित हैं। और तभी अब संघ महाराष्ट्र या झारखण्ड के चुनाव के लिए ही नहीं दिल्ली चुनाव को जीतने की तैयारी में लग लेतारा जा रहा है। मिलते टिनों

खुशी की रणधंभोर में हुई दो दिन की बैठक हुई बैठक से दिल्ली के नेता खुश हैं। यह अलग बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की लोकसभा चुनावों के दौरान संघ को लेकर बयानबाजी से संघ के नेता नाराज़ बताए जा रहे थे पर हरियाणा की जीत ने इस नारायुशी को खत्म कर दिया। चर्चा तो यह भी बताई जा रही है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी संघ अब दखल देने की जगह खुद को अलग रखे हुए हैं। भाजपा के ही कुछ नेतों यहाँ कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की संघ को लेकर बयानबाजी के बाद संघ के मोंहन भागवत की नाराजगी के बावजूद जानते थे कि उनकी यह नाराजगी हरियाणा चुनाव में जीत के बाद ख़त्म हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। संघ के ही एक अदने कढ़ के नेता तो यह भी कहने नहीं चूके कि संघ जानता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ज़ाहिर है कि 2025 में विभिन्न राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर संघ तैयारी में लग गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि रणधंभोर में हुईसंघ की मीटिंग में ही दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा विधायकों, सांसदों और प्रांत व विभाग प्रमुखों को चुनावों की तैयारी में लग जाने को कह दिया है। दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा विधायक की मानो तो संघ और पार्टी इस बार किसी भी शर्त पर दिल्ली का अपना वनबास ख़त्म करना चाहती है। अब संघ के बूते भाजपा क्या कर गुजरती है देखना बाकी है। भाजपा दिल्ली की सत्ता के लिए बेताव हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता में बैठी आप पार्टी के अलावा कांग्रेस से चुनौती मिलनी है। दिल्ली के बदलते हालातों को देख भाजपा को आप पार्टी कमज़ोर होती दिख रही है। पार्टी के कई नेता मान बैठे हैं कि आप का मुस्लिम और दलित वोट आप से खिसक कर कांग्रेस की ओर जा सकता है ऐसे में इन दोनों पार्टियों के बीच बोटों की खींचातानी से भाजपा को राजनीतिक तौर पर फ़ायदा हो सकेगा। और तभी भाजपा इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब अगर कोई यह मान रहा हो कि भाजपा की यह रणनीति लोकसभा चुनाव के बाद बनी है तो ऐसा भी नहीं है। भाजपाई सूख मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में टिकट बैंटवरों के पहले ही भाजपा दिल्ली को लेकर चिंतित थी। और तभी उसने अपने सात में से दस सांसदों ने चिन्ता तथा उम्मीदें भैजाना में उत्तरे।

ਕਰਮ ਸਿੰਹ ਠਾਕੁਰ

इसका असर न केवल उपभोक्ताओं की मानसिकता पर पड़ता है, बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब लोगों का विश्वास उठने लगता है, तो वे स्वस्थ और सुरक्षित विकल्पों की तलाश में जुट जाते हैं खाद्य सामग्री में मिलावट एक गंभीर समस्या है जो वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही है और मानव जीवन के लिए गंभीर संकट का कारण बन रही है। हर दिन सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। मिलावट का प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में भी इसका व्यापक प्रसार हो चुका है। आम जनता के बीच इसके प्रभाव को लेकर व्यापक चिंता है और इसे समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता है। खाद्य सामग्री में मिलावट के कई कारण हैं, जो इस समस्या की जड़ में मौजूद हैं। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी और आर्थिक संकट, जो कई लोगों को गलत तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है। मौजूदा समय में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, और कई लोग अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट जैसे गलत कामों में संलग्न हो जाते हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के कारण भी कुछ व्यापारी अधिक मुनाफ़ कमाने के लिए सस्ते और हानिकारक पदार्थों को असली उत्पादों में मिलाते हैं। इस तरह के व्यवहार से समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है और लोग अपने लाभ के लिए दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कानूनी सख्ती की कमी भी खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या को बढ़ावा देती है। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई कानून हैं, लेकिन इनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। मिलावटखोर अक्सर कानून के झोल का फयदा उठाकर हानिकारक कार्यों को अंजाम देते हैं। जब तक सख्त दंड और प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर काबू

A top-down view of a variety of dried grains and legumes, such as beans, lentils, and rice, displayed in numerous small, round, woven baskets. The colors range from dark brown to light beige, and the textures vary from smooth to slightly irregular.

पाना मुश्किल होगा। उपभोक्ता जागरूकता का अभाव भी एक बड़ा कारण है, जो मिलावट की समस्या को बढ़ावा देता है। अधिकांश उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच नहीं करते हैं और सर्से दामों के लालच में आकर मिलावटी वस्तुएं खरीद लेते हैं। जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ता मिलावट के हानिकारक प्रभावों को समझ नहीं पाते हैं और अनजाने में अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य खतरे में डालते हैं। ऐसे में, उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पहचान कर सकें और मिलावट से बच सकें। खाद्य सामग्री में मिलावट के कई प्रकार हैं, जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूध और दूध उत्पादों में मिलावट एक आम समस्या है। इसमें पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, यूरिया, और अन्य हानिकारक रसायनों का मिश्रण किया जाता है। इस प्रकार की मिलावट से दूध की पौष्टिकता कम हो जाती है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त मसालों में मिलावट भी एक गंभीर समस्या है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर आदि में कृत्रिम रंग, ईंट का चूरा, चॉक पाउडर और अन्य अशुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो पेट से संबंधित बीमारियों का कारण बन

सकते हैं। इसी तरह, तेल और धी में सस्ते और हानिकारक तेल मिलाकर उन्हें शुद्ध धी के नाम पर बेचा जाता है, जो हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह समस्या केवल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि सब्जियों और फलों में भी देखी जाती है। ताजगी दिखाने के लिए केमिकल्स और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, यहां तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। खासका पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिलावट की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भी मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में जहां स्वच्छ और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उम्मीद की जाती है, वहां भी मिलावट का प्रसार चिंता का विषय है। मिलावटखोर ऊंचे दामों पर वस्त्रायुक्त दवाओं, रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग फलों और सब्जियों पर कर रहे हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में लोग आम तौर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क होते हैं लेकिन अब यहां भी लोगों को मिलावट से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है मिलावट के दुष्प्रिणाम हमारे स्वास्थ्य पर गहरी प्रभाव डालते हैं। मिलावट से उत्पन्न होने वाले

## जिन पिंग के दिमाग के कोने में भारत की जीरो अंहमियत

हारशकर व्यास

भारत के प्रति चीन इच भर (हा, इच भर) न नर्म होगा, न पीछे हटेगा। इसका फिर प्रमाण 23 अक्टूबर 2024 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिन पिंग की मुलाकात है। वैश्विक राजनीति के परिपेक्ष्य में मुझे भारत के विदेश मंत्री, विदेश सचिव के बयानों से चीन के लचीले बनने की उम्मीद थी। लगा लद्धाख क्षेत्र की सीमा पर चीन अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति लौटा देगा। भारतीय सेना जिस इलाके में पैट्रोलिंग करती थी, वहां वह वापिस करने लगेगी। चीन यदि अपने कब्जाएं 2000 वर्गकिलोमीटर भारतीय क्षेत्र से सैनिक हटाता है, दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने के गतिरोध से पीछे हटती हैं तो भारत का चीन पर विश्वास बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश तब मन से चीन का दोस्त होगा। और चीन-रूस मिलकर विश्व राजनीति में अपनी जो अलग व्यवस्था बना रहे हैं उसमें भारत साझेदार या परोक्ष समर्थक होगा। वह सैनिक-सुरक्षा चिंता में अमेरिका-पश्चिमी देशों की ओर देखना रोक देगा। इससे चीन-रूस के पश्चिमी देशों के खिलाफ शक्ति परीक्षण, नई विश्व व्यवस्था, वित्तिय व्यवस्था के एजेंडे को बल मिलेगा। आखिर 140 करोड़ लोगों की आबादी का देश डालर में लेन-देन के लिए दो यातान् रुबल लिए जाने वाला है।

है। रूस उस पर आश्रित है। उसका कधा है राष्ट्रपति शी जिन पिंग जो कहेंगे वही पुतिन करेंगे पुतिन कतई शी जिन पिंग को नहीं समझा सकते हैं। दो, चीन-रूस का एकीकृत मिशन अमेरिका-पश्चिम की केंद्रीकृत धुरी के आगे अपनी नई विश्वव्यवस्था बनाना है। तीन, चीन ने इसके लिए दुनिया भर के छोटे-गरीब देशों को बैंडिंग हा पैसा दे कर उन्हें अपना मोहताज बनाया है। भारत के सर्वपड़ौसी चीन पर आश्रित है। अर्थात् वह देशों का संख्यात्मक ताकत बनाते हुए है। चार, भारत जापान, आस्ट्रेलिया जैसे देशों को चीन ने सैनिक दबाव और व्यापार के दोहरे कारणों से दुविधा चिंता तथा आयातों की निर्भरता में ऐसा फंसाया है कि भारत के विदेश मंत्री को सार्वजनिक तौर पर यह मजबूरी बतलानी पड़ती है कि यह मुद्दा (व्यापार) जटिल है और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ नहीं है। पांच, ब्रिक्स की बैठक में नेटो सदस्य तुर्की को न्यौत कर तथा मिस्त्र, इथियोपिया की सदस्यता का अर्थ है कि चीन-रूस ने उत्तर-मध्य एसिया के सभी इस्लामी देशों के अलावा पाकिस्तान से तुर्की तक फैले पूरे पश्चिम एसिया उत्तर अफिका के उस सभ्यतागत क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेने का ब्ल्यूप्रिंट बनाया है जहां इस्लामी देशों (विशेषकर यहूदी इजराइल के परिपेक्ष्य में) की गोलबंदी भविष्य में चीनी सभ्यता का खंभा हो सकती है। तीव्री चीन और ग्राम्याविशी चिन पिंग दोनों

चीन का थिकटैक जानता है 140 लोगों का भारत कभी ईस्टर्निडिया कंपनी से चलता था अब अदानी-अंबानी से चलता है। अदानी-अंबानी, कारोबारियों को मैनेज करों, उनका मुनाफा बनवाओं तो अपने आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाक भागे आएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्रालय खुद ही हैंडलाइन बना डालेंगे कि भारत और चीन पूर्वी लद्धाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त के पैटर्न को लेकर एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। वास्तविकता है ताईवान को ले कर चीन की अमेरिका से जबरदस्त ठीनी हुई है। उसकी आर्थिकी अमेरिका-योरोप की घेरेबंदी से मंदी की मारी है। वह रूस के साथ सैनिक-सामरिक-आर्थिकी की साझेदारी से दुनिया का अछूत हुआ है तो ऐसे में भारत यदि उसके मंसूबों की नई विश्व व्यवस्था में उसका साझेदार या मौन पैरोकार भी बने तो रूस-चीन के झंडे का दबदबा बढ़ेगा। जब दांव इतने ऊंचे और भविष्य दृष्टि के हैं तब लद्धाख क्षेत्र के बंजर पठार के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीन अपनी सेना को अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटा ले तो नुकसान से ज्यादा उसे फायदा है! प्रधानमंत्री मोदी कजाक जा कर राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। फिर भले हम-आप और दुनिया खोजती रहे कि भारत के सैनिक क्या सचमुच डेपसांग, गलवान, गोगरा, पैंगोन के नॉर्थ ब्लॉक और कैलाश रेंज में ऐसे ही सात ल्पावे द्वा तैयार थारेंज 2020 से

# बैंकों को विदेशियों को बेचना कितना जायज़

डा. अश्विनी महाजन

यदि यस बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी विदेशियों को बेचने का प्रस्तावित सौदा हो जाता है, तो इससे बैंकों के विनिवेश और उन्हें विदेशियों को बेचने का एक बड़ा मामला खुल सकता है वर्ष 2020 के मार्च माह में भारत के एक महत्वपूर्ण निजी बैंक, यस बैंक के निजी प्रबंधन की गतियों (भृष्टाचार सहित) के कारण लगभग दिवालिया हो गया था। लोगों का विश्वास खोने के बाद बैंक से जमाकर्ताओं ने अपनी राशि वापस लेना शुरू कर दिया जिसके चलते बैंक को अपने लेन-देन को रोकना पड़ा। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (एक सरकारी बैंक) ने 49 प्रतिशत शेयर खरीद कर उसे अपने हाथ में लिया जिससे यस बैंक में जमाकर्ताओं का विश्वास पुनः जम गया। उसके बाद यह बैंक पुनः उठ खड़ा हुआ और अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हो गया। बाद में यस बैंक ने नए शेयर जारी कर और पूंजी जुटाई, और भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत तक आ गई। स्टेट बैंक के अलावा 11 अन्य ऋणदाता संस्थाएं हैं जिनके पास यस बैंक के लगभग 9.74 प्रतिशत शेयर हैं। यस बैंक के 16.05 प्रतिशत शेयर अब जो चिनी बैंकी मालियों पर फहराएं हैं, उसमें से एकी चारी तरफ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के यस बैंक में शेयरों को बेचने की बात आगे बढ़ गई है। प्रस्तावित विदेशी निवेशक, यस बैंक के 51 प्रतिशत शेयर कब्जाना चाहते हैं ताकि उसके पास निर्णय का अधिकार आ जाए। इसके लिए हालांकि वे पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक की इस नियमानुसार शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें अगले 15 वर्षों में अपनी प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को 26 प्रतिशत तक लाना होगा, लेकिन अब वे वो भी मान गए हैं। गौरतलब है कि इस बैंक को उबारने में भारतीय स्टेट बैंक ने 7520 करोड़ रुपए का पुनः पूंजीकरण किया था। लेकिन बैंक के पुनरुद्धार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई पूंजी बढ़कर अब 18000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद न केवल जमाकर्ताओं का पैसा ढूबने से बच गया, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हुआ और इस प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक को भी 10000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत लाभ हुआ। ऐसे में इस बात पर विचार करना जरूरी है कि वया यस बैंक के 51 प्रतिशत शेयरों को चिनीय बैंकों से खरीदा जाए, जिसका उपरांत

A large, illuminated gold-colored sign spelling "BANK" in bold, three-dimensional letters is mounted on the side of a modern building. The building has a grid of dark-framed glass windows. The "B" is on the left, "A" is in the middle, "N" is on the right, and "K" is on the far right, extending beyond the frame.

मान बारने रुपए बैंक बैंक 3000 रिजर्व बैंकल गया, का क्रिया करोड़ हुआ। भी है तों को दैन

जैसे महत्वपूर्ण बैंक को विदेशी हाथों में सौंपना उचित होगा ? एलपीजी नीतियों के अंतर्गत कई सरकारी उद्यमों का निजीकरण किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में चूंकि पहले से ही निजी भारतीय और विदेशी बैंक कार्यरत थे और वे बदस्तूर चलते रहे। इसके साथ ही साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ गैर वित्तीय संस्थानों को बैंकों में बदला गया और कुछ नए बैंकों को निजी क्षेत्र में काम करने के लाईसेंस प्रदान किए गए। लेकिन इस दौरान भी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण से सरकार बचती रही। गैरतलब है कि बैंकिंग किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र है। यह बात सही है कि दुनिया में निजी और सार्वजनिक दोनों रूपों में एक साथ चैंट सामाजिक देश में ज्यादातर बैंक निजी हाथों में हैं। निजी बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि बीमा व सीमा तक ही सुरक्षित होती है। बीते साल में अमरीका में ही हजारों बैंक दिवालिय हुए, जिसके चलते जमाकर्ताओं को उनका गाढ़े पसीने की कमाई से हाथ धोना पड़े। यूरोप की स्थिति भी बहुत भिन्न नहीं है अंवहां भी आए दिन बैंकों की दिवालिया होती है। भारत एक ऐसा देश है, जहां आजादी के बाद और खास तौर पर 1969 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ब निजी बैंकों के दिवालिया होने की भी खबर अपवाद हैं। सार्वजनिक बैंकों जमाकर्ताओं की राशि डूबना तो संभव है तर्हीं उपर्युक्त दो पर्याप्त सामाजिक

संप्रभु गारंटी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त नियमन के कारण निजी बैंकों में लोगों की धन राशि काफ़ी हद तक सुरक्षित है और जब कभी कुप्रबंधन के कारण उनके दिवालिया होने की संभावना भी बनती है तो सरकारी हस्तक्षेप से उसे दुरुस्त कर दिया जाता है। पिछले दिनों यस बैंक का पुनरुद्धार उसका का जीता-जागता एक उदाहरण है। बैंकों का निजीकरण उन्हें विदेशी हाथों में सौंप कर ही क्यों : हाल ही में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को कुछ कम किया गया है। साथ ही साथ समय-समय पर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की बात को दोहराती भी रही है। लेकिन अभी तक किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निजीकरण नहीं किया गया है। आज जब देश में इस विषय पर नीतिगत चर्चा के बिना एक महत्वपूर्ण बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिग्रहीत कर ढूबने से बचाया गया था, को विदेशी हाथों में सौंपना यस बैंक के ग्राहकों, देश के वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए उपयुक्त होगा। क्या यस बैंक को विदेशी हाथों में सौंपना, एकमात्र विकल्प है या उसके अलावा भी विकल्प हैं? यदि विकल्प हैं तो उनमें से कौनसा ऐसा विकल्प है?







